संपादकीय जागरण

मंगलवार, 23 अक्टूबर, 2018 : आश्विन शुक्ल 14 वि. 2075

भोग और वैराग्य के बीच की अवस्था है त्याग

तरक्की की तस्वीर

बीते तीन सालों में सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या बढ़ना केवल यही नहीं बताता कि कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम रंग ला रही है, बल्कि यह भी प्रकट करता है कि लोगों में सरकारी तंत्र पर भरोसा बढ़ रहा है और वे अपने हिस्से का टैक्स चुकाने के लिए आगे आ रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले 2017-18 में अपनी आय सालाना एक करोड़ रुपये बताने वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या में 68 प्रतिशत की अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज की गई। इसमें नोटबंदी और जीएसटी पर अमल की भी भूमिका को देखा जाना चाहिए। हालात किस तरह बदल रहे हैं, इसे इस आंकड़े से और भी अच्छे से समझा जा सकता है कि जहां वित्त वर्ष 2013-14 में कुल 3.79 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हुए थे वहीं 2017-18 में उनकी संख्या बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई। चूंकि इस वित्त वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले नए करदाताओं का आंकड़ा सवा करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक अच्छा सिलसिला कायम हो गया है। यह सिलसिला केवल सरकारी खजाने की सेहत सुधारने वाला ही नहीं, देश की प्रगति में योगदान देने वाला भी है। यह सही है कि सवा सौ करोड़ से अधिक आबादी अथवा करीब 25 करोड़ परिवारों वाले इस देश में आयकर दाताओं की कुल संख्या 6.85 करोड़ कोई बहुत अधिक नहीं, लेकिन इससे बेहतर और कुछ नहीं कि सक्षम लोग आयकर के दायरे में आना उचित समझ रहे हैं। भले ही ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध न हो कि कितने लोग सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के चलते इस दायरे में आ रहे हैं और कितने स्वेच्छा से, लेकिन जो भी स्वतः आ रहे हैं वे साधुवाद के पात्र हैं।

देश में आयकर दाता बढ़ने के लिए यह भी आवश्यक है कि समृद्धि का विस्तार से तेजी हो और ऐसा तब होगा जब सभी समर्थ लोग टैक्स चुकाएंगे। यह स्वागतयोग्य है कि सरकार का आधे से ज्यादा खजाना आयकर विभाग भर रहा है। जब सरकार के खजाने में पर्याप्त पैसा होगा तभी वह जन कल्याण के साथ विकास की योजनाओं पर अमल कर सकेगी। ऐसी ही योजनाएं निर्धन तबके को गरीबी रेखा से ऊपर लाती हैं और समय के साथ इस तबके के कुछ लोग भविष्य के आयकर दाता बनते हैं। चूंकि ऐसे आंकड़े सामने आ चुके हैं कि बीते एक दशक में अपने देश में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं इसलिए इस शिकायत के लिए कोई गुंजाइश नहीं कि सरकारें आखिर सरकारी खजाने का करती क्या हैं? वे राष्ट्र को सक्षम-समर्थ बनाने के उपाय करती हैं और उन्हें आसानी तब होती है जब आम लोग आर्थिक नियम-कानूनों का भी स्वेच्छा से पालन करते हैं। यह एक हकीकत है कि जिन देशों के आम लोग नियम-कानूनों के प्रति जितनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं वे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। भारत को तेजी से आगे बढ़ते हुए विकसित देशों की कतार में आना है तो तमाम अन्य बातों के साथ यह भी आवश्यक है कि जो समर्थ हैं वे टैक्स चुकाएं।

अति सक्रियता के खतरे

कभी रामजन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी नेताओं में शामिल रहे डॉ.प्रवीण भाई तोगड़िया की मौजूदा सक्रियता असामान्य प्रतीत होती है। कुछ साल पहले विहिप अध्यक्ष के रूप में भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर चुके तोगड़िया इस समय कुछ इस तरह जिद कर रहे हैं, मानो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर ही चैन लेंगे। इसमें दो राय नहीं कि डॉ.तोगड़िया की तरह करोड़ों अन्य देशवासी भी राम मंदिर निर्माण की बाट जोह रहे हैं यद्यपि उनमें से अधिकतर इसे लेकर राजनीतिक नेतृत्व की विवशता भी समझते हैं। यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और फैसला आने पर स्वाभाविक रूप से व्यापक जन-प्रतिक्रिया होना तय है। यह भांपते हुए खुद न्यायालय संवेदनशील पहलुओं पर नजर रखकर इस मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय पूर्व इसी संवेदनशीलता के मद्देनजर सुझाव दिया था कि दोनों पक्ष न्यायालय के बाहर सहमति बनाकर यह विवाद हल कर लें। तोगड़िया केंद्र सरकार पर तरह-तरह की तोहमत मढ़ रहे हैं। तोगड़िया की अति-सक्रियता के पीछे उनका संघ परिवार से मनमुटाव भी है।

यह विवाद यदि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नहीं सुलझता है तो इसके निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए

शायद यही वजह है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा कोई भी प्रमुख संत तोगड़िया के साथ नहीं है। परमहंस रामचंद्र दास और अशोक सिंहल इस आंदोलन के शलाका-पुरुष थे पर उन्होंने भी डॉ. तोगड़िया जैसा हठयोग कभी नहीं किया। देश का हर संवेदनशील और विवेकशील नागरिक चाहता है कि यह विवाद यदि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नहीं सुलझता है तो इसके निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नई शिक्षा नीति को लेकर हो रही देरी केंद्र सरकार के सुस्त रवैये का परिणाम है?

आज का सवाल

क्या सीबीआइ में शीर्ष अधिकारियों के बीच कलह से इस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता प्रभावित होगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की चुनौती

डॉ. भरत झुनझुनवाला

ईरान पर प्रतिबंध लगाने से यह संभावना बढ़ गई है कि विश्व के प्रमुख देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में रखना शुरू कर दें। ऐसा ही भारत को करना चाहिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बैंकों के माध्यम से ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने ईरान द्वारा भेजे गए तेल के टैंकरों का बीमा करने के लिए भी अमेरिकी कंपनियों को मना किया है। ट्रंप का उद्देश्य है कि ईरान के लिए तेल का निर्यात मुश्किल बना दें। तब ईरान की आय घटेगी, लोगों में असंतोष बढ़ेगा और ईरान को अमेरिका के बताए अनुसार अपने परमाणु कार्यक्रम में और कटौती करनी होगी। कुछ अर्सा पहले ईरान ने अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देशों से यह करार किया था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम का दायरा घटाएगा। वैश्विक जांच एजेंसियों के अनुसार ईरान ने उस समझौते का पालन किया है। ट्रंप पूर्व के समझौते को निरस्त करके और कठिन समझौते को लागू कराना चाहते हैं, लेकिन चीन, यूरोप, भारत और रूस को ईरान का तेल चाहिए। वे यदि ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो विश्व में तेल की आपूर्ति कम होगी। इससे तेल के दाम बढ़ेंगे और इन देशों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए ये देश चाहते हैं कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से तेल की खरीद जारी रहे। इस दिशा में 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने तेल का निर्यात कैसे जारी रखा था, इसे देखना जरूरी है।

तब ईरान ने अपना एक खाता यूको बैंक की कोलकाता शाखा में खोला था। भारतीय तेल आयातकों ने तेल का लगभग आधा भुगतान रुपयों में यूको बैंक की इस शाखा में ईरान सरकार के खाते में जमा करा दिया। इस रकम का उपयोग ईरान ने भारत से बासमती चावल जैसी सामग्री खरीदने के लिए किया। इस प्रकार भारत ने ईरान से तेल का आयात और ईरान ने भारत से बासमती चावल का आयात सीधे रुपये के माध्यम से किया। इस द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की कोई भूमिका नहीं रह गई। अब भारत ने ईरान के दो बैंकों को भारत में अपनी शाखा खोलने की स्वीकृति दे दी है। इन बैंकों में ईरान से खरीदे गए तेल का भुगतान भारत रुपयों में कर सकता है। ईरान उस रकम का उपयोग भारत से माल का आयात करने में कर सकता है। अमेरिकी बैंकों के माध्यम से यह भुगतान नहीं होगा। यह अमेरिकी प्रतिबंधों के बाहर रहेगा। ईरान भारत से माल का आयात न करना चाहे तो भी रास्ता है। मान लीजिए ईरान ने भारत को तेल निर्यात किया और उस रकम से ईरान जर्मनी से ट्रक खरीदना चाहता है। ऐसे में भारत द्वारा ईरान को भुगतान यूरो में किसी जर्मन बैंक में डाला जा सकता है। उन यूरो का उपयोग ईरान द्वारा जर्मनी से ट्रक खरीदने के लिए हो सकता है। इस प्रकार अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध मूल रूप से निष्प्रभावी हो सकते हैं।

जिस प्रकार हम अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित हैं उसी प्रकार चीन, यूरोप और रूस भी। इन देशों ने मन बनाया है कि एक वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था बनाई जाए जिसमें अमेरिकी बैंकों का हिस्सा न हो। वर्तमान में विश्व के वित्तीय लेनदेन में डॉलर का हिस्सा 39 प्रतिशत और यूरो का 35 प्रतिशत है। यदि यूरोपीय देश वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था बना लेते हैं तो अमेरिका का हिस्सा और कम हो जाएगा। इससे विश्व अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाएगा। ईरान पर प्रतिबंध लगाना एक और कारण से अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।

अवधेश राजपूत

अमेरिकी सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ओबामा के समय अमेरिकी सरकार का वार्षिक घाटा 600 अरब डॉलर था। वर्तमान में यह बढ़कर 890 अरब डॉलर हो गया है। वित्तीय घाटे का अर्थ हुआ कि अमेरिकी सरकार की आय कम और खर्च ज्यादा है। इस बढ़े हुए खर्च से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। वह बड़ी कंपनियों को छूट दे रहे हैं जिससे उनके द्वारा अधिक लाभांश का भुगतान किया जा रहा और शेयर बाजार उछल रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीन प्रतिशत की तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की यह गति ऋण पर आधारित है। वर्तमान में अमेरिका ने 21,000 अरब डॉलर की विशाल राशि ऋण के रूप में ले रखी है। इसमें चीन और जापान प्रत्येक द्वारा 1,000 अरब डॉलर की राशि अमेरिका में जमा कराई गई है। अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अमेरिका के लिए जरूरी है कि उसे भारी मात्रा में ऐसा विदेशी ऋण निरंतर मिलता रहे।

सभी देश अपने बाहरी व्यापार को संचालित करने के लिए कुछ रकम अंतरराष्ट्रीय बैंकों में जमा कराकर रखते हैं जिसे 'विदेशी मुद्रा भंडार' कहा जाता है। इस भंडार को बनाए रखने के लिए अब तक अधिकांश देश अपनी मुद्रा को अमेरिकी बैंकों में जमा रखते थे, लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने से अमेरिका की विश्वसनीयता में गिरावट आई है। मिसाल के तौर पर रूस ने 150 अरब डॉलर की राशि विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में अमेरिका में जमा करा रखी थी। इसमें से उसने 85 अरब डॉलर निकाल कर उसे दूसरी मुद्राओं में जमा कराया है। यदि चीन, जापान, भारत समेत अन्य देश भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अमेरिकी डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं अथवा सोने में निवेश करते हैं तो वर्तमान में अमेरिका को जो ऋण मिल रहा है उसका प्रवाह उलट जाएगा। घाटा पूरा करने के लिए अमेरिकी सरकार को ऋण मिलना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिकी अर्थव्यवस्था घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगी। ईरान पर प्रतिबंध लगाने से यह संभावना बढ़ गई है कि विश्व के प्रमुख देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में रखने के स्थान पर दूसरी मुद्राओं में रखना शुरू कर देंगे। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हो सकती है।

वर्तमान में अमेरिका विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध शेष विश्व के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं,लेकिन दीर्घकाल में यह परिस्थिति पलट सकती है। यदि यूरोपीय देशों ने वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था बना ली अथवा विश्व के प्रमुख देशों ने अपना विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में रखना शुरू कर दिया तो फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस परिस्थिति में भारत को अपना रास्ता बनाना है। तात्कालिक रूप से हमें ईरान से तेल आयात करते रहना चाहिए। हम ईरान को इसके लिए मनाएं कि वह रुपये में भुगतान स्वीकार करे। उसके एवज में यदि हमें ईरान को कुछ अधिक दाम भी देने पड़ें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ईरान द्वारा रुपये में किए गए इस भुगतान का इस्तेमाल भारत से वस्तुओं का आयात करने के लिए किया जाएगा। इससे भारत के निर्यातकों का धंधा बढ़ेगा। दीर्घकाल में भारत को यूरोपीय देशों द्वारा बनाए जा रहे वैकल्पिक बैंक का साथ देना चाहिए और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर के बजाय दूसरी मुद्राओं में रखना चाहिए। ऐसा करने से अमेरिका पर दबाव पड़ेगा और हम बहुध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ेंगे। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद हम ईरान से तेल की खरीद जारी रख सकेंगे। तब तेल के बढ़ते दामों से जनता को भी राहत मिलेगी।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

एकता का बोध कराती प्रतिमा

शीघ्र ही सरदार पटेल की प्रतिमा उनके व्यक्तित्व के अनुरूप विराट रूप में होगी

राष्ट्र जीवन के संदर्भ में व्यक्ति का जीवनकाल बहुत छोटा होता है, परंतु कुछ राष्ट्र निर्माताओं की छाप सदियों तक कायम रहती हैं। अमेरिका के राष्ट्र जीवन में जैसे अब्राहम लिंकन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र जीवन में नेल्सन मंडेला का जैसा स्थान बना है, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की अमिट छाप सदियों तक भारत के राष्ट्र जीवन में रहने वाली है। राजनीतिक जीवन में श्रेय लेने को लेकर होने वाली हेराफेरी स्वाभाविक है, लेकिन यह उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अक्सर कुछ सत्तासीन शासक पूरे का पूरा श्रेय स्वयं लेने के प्रयासों में तमाम अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जन स्मृति में पहुंच एवं उसके कायम होने से रोकने का सतत प्रयास करते हैं।

ऐसे ही कारणों से भारत में भी अनेक महान व्यक्तित्व उनके योगदान के अनुरूप स्थापित नहीं होने दिए गए। स्वतंत्रता संघर्ष के सिपाही सरदार पटेल उन्हीं शख्सियतों में से एक हैं। राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसके निर्माण में उनका योगदान बहुत बड़ा है, किंतु यह भी एक सच्चाई है कि उनके कद के दायरे को हमेशा घटाने का ही प्रयास किया गया। उनके योगदान के अनुरूप वडोदरा से 90 किलोमीटर दूर नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध पर साधू बेट में अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होने वाली है। इसके शिलान्यास के समय गुजरात के मुख्यमंत्री और अब अनावरण के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और निर्णय से यह प्रतिमा प्रकाश-स्तंभवत सदियों तक यह खड़ी रहेगी।

सरदार पटेल के महती योगदान को समझने के लिए कुछ सवालों के जवाब तलाशाने की कोशिश करें तो आसानी होगी। यदि सरदार पटेल नहीं होते तो क्या स्वतंत्र हुआ भारत एकजुट बना रहता? अंग्रेज भारत को कई टुकड़ों में विभाजित कर एक खंडित देश के रूप में छोड़कर जाना चाहते थे। बिना भौगोलिक संपर्क के भी, पाकिस्तान हमारे बीच-बीच में होता? ऐसे में तमाम टुकड़ों में बंटे इन हिस्सों के साथ आज हम कितने पाकिस्तानों से लड़ रहे होते?

अपने कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों के दर्शन के लिए जैसे आज हम चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का वीजा लेकर जाते है, क्या उसी तरह सरदार पटेल के गुजरात के जूनागढ़ में, तेलंगाना के हैदराबाद में, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हमें वीजा लेकर जाना पड़ता? सरदार पटेल के काम का आकलन 1947-1950 के वर्षों और उन स्थानों से गुजरे बिना नहीं हो सकता जहां से उनका वास्ता पड़ा। देश-विदेश के अनेक विद्वान भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है जिसकी राष्ट्रीयता का आधार, एक राज्य इकाई नहीं, एक संस्कृति है। क्या 565 अलग-अलग राज्य इकाइयों के साथ, वर्तमान भारत विश्व में अपना स्थान बना पाता? राष्ट्र राज्य सिद्धांत को मानने वाले लोग एक भूमि के टुकड़े पर एक शासन की इकाई स्थापित होने पर ही राष्ट्र के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। यही वर्तमान विश्व की हकीकत भी है। इस सांस्कृतिक-राष्ट्र को, राष्ट्र राज्य बनाने का श्रेय केवल और केवल सरदार पटेल के नाम है। यह राष्ट्र-राज्य के वर्तमान स्वरूप के बिना अपनी नियति को पाने में विफल रहता है। सांस्कृतिक राष्ट्रों का भी अंतिम ध्येय एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा होने का होता है, जिसका शासन तंत्र भी एक हो।

ओमप्रकाश धनखड़

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत निर्माण की एक कथा के साथ ही भारत को एकजुट करने वाले शिल्पी को श्रद्धांजलि भी है

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्तमान भारत के भारत बनने की कथा होने के साथ ही उस शिल्पी को श्रद्धांजलि भी है जिसने स्वतंत्रता के समय भारत को एकजुट कर राष्ट्र के रूप में खड़ा किया था। यह इतिहास के पन्नों को नई पीढ़ी के सामने खोलने की पाठशाला भी है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा खड़ी होकर खुद एक इतिहास की भी रचना करने जा रही है। यह देश की भावी पीढ़ी को अपने अतीत से रूबरू कराएगी जिसे जानना उनके लिए बेहद आवश्यक है।

सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता का जो कार्य जीवन में करके गए, वही नव भारत के राष्ट्रीय-तीर्थ के रूप में खड़ी होने वाली यह प्रतिमा करेगी। सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा भारत के एक-एक गांव से आए किसान के प्रयुक्त लोहे और हर गांव के देवस्थान से आई भावनाओं से भरी पवित्र मिट्टी से जो बनी है। यदि सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व में उतरेंगे तो सरदार की ऊंचाई से भी जुड़ सकेंगे जो अपनी प्रतिमा के समान ऊंची है। भारत का यह नवतीर्थ राष्ट्र के शौर्य का वर्तमान पीढ़ी से परिचय कराएगा और इजरायल के यादवशम् म्यूजियम की तरह छुपाए गए इतिहास के पन्नों को खोलेगा। सरदार पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर अब उनकी प्रतिमा लघु नहीं रहेगी, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप विराट रूप में खड़ी होगी।

(लेखक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लौह मिट्टी संग्रहण के राष्ट्रीय कोर्डिनेटर और हरियाणा के कृषि एवं पंचायत मंत्री है)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं को निखारो

बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि 'आप वही हैं, जो आपकी वास्तविक कामना है। जैसी आपकी मनोकामना होती है, वैसी ही आपकी इच्छा दिखती है। जैसी आपकी इच्छा होती है, वैसा ही आपका काम होता है। जैसा आपका काम होता है, वैसा ही आपका भाग्य होता है।' कुछ लोग भाग्य को पूर्व जन्मों का योग मानते हैं तो कुछ सितारों का खेल। जबकि वास्तविकता यह है कि भाग्य इसी जन्म में आपके संघर्षों, सद्कार्यों और मेहनत का परिणाम होता है। जो व्यक्ति कार्य करने का जोखिम ही नहीं उठाता, वह कैसे जीत सकता है? वह व्यक्ति काम शुरू न करने के डर को जीत लेता है और धीरे-धीरे ही सही अपने पथ पर बढ़ता रहता है।

कुछ लोग स्वयं की ओर ध्यान देने के बजाय दूसरे के व्यक्तित्व एवं कार्यों पर लगातार ध्यान देते हैं और ईर्ष्यावश उन्हें नीचे गिराने का प्रयास करते रहते हैं। एक व्यक्ति अपने मकान का निर्माण करते समय दूसरों के घरों पर कम ध्यान देता है और अपने मकान को मजबूत एवं भव्य रूप देने में लगा रहता है। जब हम ईंट और मिट्टी से बने घर के निर्माण में पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो अपने व्यक्तित्व रूपी घर में हम ऐसा करने से क्यों चूक जाते हैं? अधिकतर व्यक्ति अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखारने के बजाय दूसरे के व्यक्तित्व की ताक झांक करने में अपना समय नष्ट करते हैं। हो सकता है इससे दूसरे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचे, लेकिन स्वयं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है।

जो व्यक्ति तुच्छ बातों और व्यर्थ के बखेड़ों से दूर रहते हैं, वे एक न एक दिन अवश्य ही ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन नहीं होता। इसके लिए एक दम से छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं है, धीरे-धीरे ही चलें, लेकिन सही मार्ग पर चलें। जो व्यक्ति स्वयं को निखारने में लगता है वह स्वयं के साथ ही दूसरों को भी निखार देता है, जबकि जो व्यक्ति दूसरों पर नजर रखता है, उनसे ईर्ष्या करता है वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता। प्रगति का पहला सूत्र यही है कि स्वयं को निखारो, तराशो और अपनी कमियों को दूर करो।

रेनू सैनी

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

नाम नहीं सोच बदलने की जरूरत

परिवर्तन नहीं पुनर्स्थापना है प्रयागराज शीर्षक से लिखे अपने लेख में हृदयनारायण दीक्षित ने प्रयाग के अर्थ का बखान किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम लगभग 443 साल बाद फिर से बदलकर प्रयागराज क्यों किया, यह तो वही अच्छी तरह से जानती है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी शहर का सिर्फ नाम बदल देने से उसके अच्छे दिन नहीं आने वाले। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सभी के अपने-अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से अब उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उस शहर के निवासियों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी? विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था 'नाम में क्या रखा है? किसी चीज का नाम बदल देने से भी चीज वही रहेगी। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, गुलाब ही रहेगा।' यहां यह बात भी सोचने वाली है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में यहां इस तरह की बातें ये दिखाती हैं कि हमारी सोच सिकुड़ती जा रही है। जाहिर है हमें नाम नहीं सोच बदलने की जरूरत है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

लाल किले पर झंडारोहण

पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर दोबारा झंडा फहराया है। यह एतिहासिक घटना है। यह झंडा आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस के अवसर पर फहराया गया है। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसमें भारत के पुरुष और स्त्री दोनों शामिल थे। बाद में नेता जी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में कमान सौंप दी। आजाद हिंद फौज के 75 साल पूरे होने के अवसर पर यह तिरंगा फहराया गया है। सरदार पटेल ने अगर देश की विभिन्न रियासतों को भारत में समाहित नहीं किया होता तो काफी हिस्सा भारत से अलग हो गया होता। आजादी के महान सपूत चाहे चंद्र शेखर आजाद हों या फिर भगत सिंह आजाद इन्हें यथोचित सम्मान नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को सलाम किया है, यह अच्छी बात है।

jaidevrathee@gmail.com

ताकि फिर ऐसा न हो

अमृतसर जंक्शन के पास हुई घटना एक आधुनिक समाज के रूप में हमारे रवैये पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। हताहतों की बड़ी संख्या बताती है कि दुर्घटना से पहले पटरी पर कैसी भीड़ जमा रही होगी। रावण के पुतले को आग के हवाले किया जा चुका था। दर्शक पटाखों की आवाजों के बीच जलते पुतलों को देखकर रोमांच महसूस कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर अपने मोबाइल फोन पर इन पलों को कैद करने में लगे थे। ऐसे में पटरी पर आती ट्रेन की आवाज उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं दी। घटना का अहसास तब हुआ, जब कहर उन पर टूट चुका था। हादसे के बाद हर संबंधित पक्ष हाथ झाड़कर किनारे खड़ा है। अब कम से कम यह तो देखा ही जाना चाहिए कि इस तरह की घटना को कैसे रोका जा सकता है, जिससे दोबारा कहीं इसकी पुनरावृत्ति न हो।

diwakardasy3806@gmail.com

रोहित की उपलब्धि

भारत- वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली के साथ-साथ रोहित ने भी अपना दमखम दिखाया। रोहित ने भारत को जीत दिलाने के साथ ही एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वह एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक बार 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। रोहित की इस उपलब्धि पर सबको गर्व है।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

'मी टू' के बाद अब 'मैन टू'

'मी टू' अभियान के तहत महिलाओं का बढ़-चढ़ कर आगे आना अच्छा कदम है। इसके द्वारा जिन महिलाओं का दशकों पहले उत्पीड़न हुआ था वे अपने को सामने ला रही हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इसमें कुछ पुरुषों को बेवजह फंसा कर महिलाएं अपनी पुरानी दुश्मनी भी निकाल रही हैं जो पुरुषों के लिए न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। 'मी टू' अपनी जगह पर अच्छा प्लेटफार्म है जिस पर चलकर उत्पीड़ित महिलाएं अपनी आवाज़ उठाकर न्याय के लिए गुहार लगा सकती हैं, लेकिन इसकी आड़ में खेले जा रहे खेल से कितने निर्दोष पुरुषों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए अब पीड़ित पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए ही 'मैन टू' का प्लेटफार्म शुरू किया गया है। जहां हर पुरुष, महिलाओं के द्वारा किए जा रहे शोषण या उत्पीड़न को समाज के सामने ला सकते हैं। लेकिन जो डर आज मी टू से है वही डर मैन टू में भी हो सकता है। इसमें भी कोई पुरुष रंजिशन किसी महिला पर आरोप लगा सकता है और उसको बदनाम कर सकता है। इसीलिए चाहे मी टू हो या फिर मैन टू किसी को सही तरीके से परखना बहुत मुश्किल है और इसकी सत्यता की जांच करना कठिन है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

खुशी की जगह विरोध

सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है कि धर्म के आगे कानून कमजोर होता नजर आ रहा है। वहां इस फैसले को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है और वे इसका विरोध कर रहे हैं। यह एक ऐसा फैसला था जिसको लेकर लोगों में खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन इसका दूसरा रूप देखने को मिल रहा है।

आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज दिल्ली विवि

ट्वीट-ट्वीट

एक ऐसा काम जो कांग्रेस 60 साल में भी न कर पाई, पर मोदीजी ने पांच साल में कर दिखाया! सीबीआइ से सीबीआइ पर ही छापा पड़वा दिया। वाह मोदीजी वाह!

रणदीप सिंह सुरजेवाला@rssurjewala

सीबीआइ विवाद एक संस्थान की विश्वसनीयता पर गहरा आघात है। इसके लिए तत्काल सुधार की दरकार है। संगठन से बाहर के किसी बेहतरीन रिकॉर्ड वाले प्रतिष्ठित शख्स को इसकी कमान सौंपने से बात बन सकती है।

वेद मलिक@Vedmalik1

भारतीय विदेश सेवा के 2018 के बैच में शामिल 25 अधिकारियों में से 16 इंजीनियर और दो डॉक्टर हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या वे अच्छे राजनयिक बन पाएंगे या नहीं, लेकिन जरा भारत के सामाजिक-आर्थिक तंत्र की तस्वीर देखिए जहां इंजीनियर अपने मुख्य कौशल को तिलांजलि दे रहे हैं जो नए आविष्कारों से लेकर बुनियादी ढांचा और विनिर्माण में काम आ सकता था।

केसी सिंह@ambkcsingh

पेट्रोल पंपों की हड़ताल को भाजपा की साजिश बताने वाले केजरीवाल यह क्यों नहीं बताते कि पेट्रो उत्पादों पर वह एनसीआर में सबसे ज्यादा वैट ले रहे हैं। प्रति लीटर पेट्रोल पर 22 रुपये से अधिक। आखिर उनके समोसों का खर्च किसी को तो उठाना पड़ेगा।

कंचन गुप्ता@KanchanGupta

जनपथ

मौका मिलते ही दिखा जो जम्मू-कश्मीर,
लिखने को तैयार है वो अपनी तकदीर।
वो अपनी तकदीर भा रही डेमोक्रेसी,
हो बीजेपी साथ चहे निर्दल-कांग्रेसी।
आया जबहिं चुनाव लगाया जमकर चौका,
ठेंगे पर आतंक मिले यदि उसको मौका।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 98